10/03/2025

आकाशवाणी ईटानगर

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अरुणाचल बजट 2025 को आकार देने में व्यावहारिक योगदान के लिए जनभागीदारी योजना के विजेताओं की घोषणा की। श्री खांडू ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए मेजिर नाबाम को कौशल विकास और रोजगार सृजन पर उनके सुझावों के लिए सम्मानित किया गया है। सुश्री मोरयुम ङुपोक को सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और समावेशी शिक्षा पर उनके सुझावों के लिए एवं सोनम सेतन को स्वच्छ और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के उनके विचारों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने के लिए अरुणाचल बजट वेबसाइट लॉन्च की और सभी को मुख्य हाइलाइट्स और अधिक जानकारी के लिए http://arunachalbudget.in पर विजिट करने को आह्वान किया।

0000000000000000000000

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मामलों के प्रभारी मंत्री चाउना मेन ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग चालीस करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के आवंटन की तुलना में 11.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट समावेशी विकास सुनिश्चित करने और राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन वृद्धि पर केंद्रित है।

बजट में प्रमुख आवंटनों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए तीन सौ सत्तर करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 3,000 करोड़ रुपये, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1112 करोड़ रुपये, मिशन अंत्योदय के लिए चार सौ बासठ करोड़ रुपये, कौशल विकास के लिए 106 करोड़ रुपये और स्वदेशी मामलों के लिए 60 करोड़ रुपये शामिल किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, केंद्रीय बजट के अनुरूप, इस वर्ष का बजट विकसित अरुणाचल के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां सरकार शून्य-गरीबी, 100% गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, उच्च-गुणवत्ता, सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, सार्थक रोजगार के साथ 100% कुशल श्रम, आर्थिक गतिविधियों में 70% से अधिक महिलाएं और राज्य के किसानों को और बढ़ावा देना शामिल है।

0000000000000000000000

अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईएएस अधिकारी इंद्रा मालो को केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव के समकक्ष पैनल में शामिल किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से इंद्रा मालो को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी उपलब्धियां राज्य के लिए बहुत गर्व की बात हैं और महत्वाकांक्षी सिविल सेवकों को प्रेरित करती हैं। महाराष्ट्र कैडर की 1999 बैच की आईएएस अधिकारी इंद्रा मालो की दृढ़ता और समर्पण की यात्रा शासन और सार्वजनिक सेवा में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है।

0000000000000000000000

स्वास्थ्य सेवा उप निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम अधिकारी, डॉ. के टी मुलुंग ने आज नाहरलगुन में मलेरिया पर 3 दिवसीय राज्य समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य में पिछले आठ वर्षों से मलेरिया से संबंधित चल रही रोकथाम और नियंत्रण पहलों की सफलता के तहत किसी की भी मौत की सूचना नहीं है। बैठक के दौरान, डॉ. मुलुंग ने राज्य के मलेरिया उन्मूलन प्रयासों की जानकारी सांझा कि जिसमें एनुअल पैरासाईट इंडेक्स 1 से नीचे बना हुआ है, जो प्रभावी नियंत्रण उपायों को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश को मलेरिया उन्मूलन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक होने के लिए वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र से मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि 2022 और 2024 के बीच दो अतिरिक्त जिलों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, जिससे मलेरिया मुक्त जिलों की कुल संख्या बढ़कर 16 हो गई।

0000000000000000000000

राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, दोइमुख के फाईन आर्ट्स एण्ड म्यूसिक डिपार्टमेंट द्वारा एक्प्लोरिंग ट्रेडिशनल वूड कार्विंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश के मोरुंग, फ्यूनरल रिचुएल्स एण्ड फेस्टिविटीस ऑफ तिराप एण्ड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्स पर पांच दिवसीय लकड़ी की नक्काशी कार्यशाला शुक्रवार को संपन्न हुई। कार्यशाला का आयोजन तिराप जिले के रिसोर्स पर्सन श्री मनवांग लोवांग के नेतृत्व में किया गया। श्री लोवांग स्कालपचर में राज्य के पहले बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स डिग्री धारक हैं।

0000000000000000000000

मौसम विभाग ईटानगर ने कल और परसों के लिए राज्य के वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, कुरुंग कुमे, क्रा दादी, कामले, लोअर सुबनसिरी, पापुम पारे, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग, अपर सियांग, लोअर दिवांग वैली, दिवांग वैली, अंजाव, लोहित, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले 24 घंटों में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।

000000000000000000000

लोकसभा ने आज बिल ऑफ लैडिंग, 2024 को पारित करने के लिए विचार किया। इस बिल को जारी करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने वाले भारतीय बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम, अट्ठारह सौ छप्पन को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सदन में विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक शिपिंग क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 2021 में पोर्टल लॉन्च किया गया था। जिनमें कुल पंजीकृत श्रमिकों में से तिरपन प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं।

00000000000000000000